

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: The situation is very serious. The House must be concerned about it if the Minister is not available. The calling attention is accepted and it is not being replied.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Hardship Another hardship!

**RE. HARDSHIPS FACED BY
COCONUT GROWERS DUE TO
DISEASE AND CONSEQUENT
DRASTIC FALL IN PRICES**

SHRI J. CHITHARANJAN (KERALA): I am grateful to you for having allowed me to bring to the notice of this House the plight of the coconut cultivators. Madam, in tens of lakhs of acres these coconut trees are affected by Wilt. In fact, this disease has manifested itself or it first came to notice some decades ago. Since then, the Government of India has taken certain steps to find out the remedy for it. Certain issues have since been organised and the scientists have been asked to find out reasons for such a disease and how to eradicate it. But, so far the scientists have not succeeded in finding a remedy for it. Therefore, year after year this disease is spreading to new areas, and with the consequent result, tens of lakhs of trees have reached a stage where it cannot give any yield at all. In the remaining trees also, the productivity is going down with the consequent result, agriculturists engaged in cultivation of coconut trees are in a very miserable plight. Now, certain measures will have to be taken. One of the measures that is to be taken is to cut down the trees which are seriously affected by this disease, and then in their places new saplings will have to be cultivated. In that case, it may take seven to eight years to get yield from those trees. Unless sufficient financial assistance is given to agriculturists, they cannot do this. There is a Board called Coconut Development Board. But

unfortunately, that Coconut Development Board is not paying attention to this problem and is not giving sufficient help to the agriculturists. My proposal is that it may function like the Rubber Board. In the case of Rubber Board, if new areas are being brought under cultivation, peasants are being given necessary financial help by way of grants as well as loans. In the same way, when the old trees are being cut and new saplings are being cultivated, then also they are being given financial assistance. So, such type of assistance is being given by the Rubber Board. Therefore, I would request the Government to take measures to see that the Coconut Development Board also functions like the Rubber Board and gives the necessary assistance to the cultivators.

In the same way, another point to be noted is the import of copra from other countries. It is another factor which leads to fall in the prices of coconut. That should also be stopped. Madam, through you, I would like to bring to the attention of the Government the problem being faced by coconut cultivators. I hope the Government will take necessary steps.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Manohar Kant Dhyani. I have 13 more Zero Hour or Special Mentions before me. If the Members speak fast, we can finish it and then adjourn the House for lunch.

**RE: SITUATION ARISING OUT OF
NON-FUNCTIONING OF PDS IN
UTTARANCHAL/UTTARAKHAND
OF U.P.**

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, जिसको अब उत्तराखंड या उत्तरांचल के नाम से हम लोग पहचान रहे हैं, में अन्न के भीषण अकाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदया, पिछली बार, इसी सदन में खाद्य मंत्री जी ने देश के गरीब लोगों के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी और कहा था कि जो गरीब की रेखा के नीचे के लोग हैं

उन्हें वह सस्ता अन्न उपलब्ध करायेंगे। ऐसी कोई योजना जो जन-हित की होती है वह सर्वोग्राही होती है। सारे देश के लोग इसे चाहते हैं। लेकिन उत्तरांचल में इसका परिणाम ठीक नहीं रहा है। महोदया, मेरे हाथ में एक अखबार है। इसकी हेडिंग है “नई वितरण प्रणाली से उत्तराखंड में खाधान संकट”। अब मैं इसमें से दो-तीन चीजें सर्वे के रूप में पढ़ना चाहता हूँ। झुर्रियों से भरी 60 वर्षीय उज्ज्वला देवी के बूढ़े चेहरे पर भविष्य को लेकर आशंकाओं की छाया है। खाद्य संकट से पैदा हुई इन आशंकाओं की छाया है। खाद्य संकट से पैदा हुई इन आशंकाओं के बीच वह सवाल करती है कि “राशन नहीं मिली तो हमारे बच्चों का क्या होगा?”

केंद्र व राज्य सरकारों के मुखियाओं को कोसती हुई डंडासली गांव की यह वृद्ध कहती है कि जब से गुजरात और मायावती कुर्सी पर बैठे हैं तभी से राशन आना बंद हुआ है। उज्ज्वला देवी ही नहीं, नवागर गांव के 65 वर्षीय वृद्ध मोहर सिंह हों या चामनी गांव के 76 वर्षीय खुशाल सिंह, सबकी जुबान पर एक ही प्रतिक्रिया है, “ऐसा कभी नहीं हुआ”। वे 1966-67 के भारी अन्न संकट के दौर को याद करते हुए कहते हैं, “तब कम से कम सरकार ने पेट भरने के लिए ज्वार तो भेजा था”। खुशाल सिंह कहते हैं कि तब भूखों मरने की नौबत नहीं थी। पर्याप्त मात्रा में ज्वार राशन की दुकानों में रहता था।

मेरा आग्रह यह है कि यह स्थिति वहां पैदा हो गई थी कि दो महीने तक खाधान की दुकानों ने खाधान बेचना बंद कर दिया था। यह कहा गया कि केन्द्र सरकार दाम बढ़ाने वाली है, इस कारण से हम खाधान नहीं बेच सकते हैं। गोदामों ने छोटी दुकानों और खुदरा दुकानों को अन्न नहीं दिया। बाद में केन्द्र ने दाम बढ़ाए तो उन्होंने तीन किलो प्रति राशन कार्ड पर अन्न देना शुरू किया। तीन किलो गेहूं और एक किलो चावल देना शुरू किया जबकि 1992-93 में जब नरसिंह राव जी की सरकार थी, उसने यह व्यवस्था की थी कि एक हजार ब्लाक पूरे देश में पहचाने गये थे जो विषम भौगोलिक परिस्थिति में हैं, जहां अन्न कम पैदा होता है, उसके लिए व्यवस्था की गई थी कि वहां 10 किलो गेहूं और 7 किलो चावल एक यूनिट अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के लिए निश्चित किया गया था। मैं नहीं समझता कि इस समय क्या कठिनाई आई है कि यह थोड़ा सा गेहूं या चावल गरीबों को देने की बात आई जिससे पूरी व्यवस्था विश्रुंखलित हो गई। इससे उस क्षेत्र में आक्रोश पैदा हो गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह हुई है कि अभी प्रधान मंत्री जी आंकड़ा बता रहे थे उत्तर प्रदेश में 6

प्वाइंड कुछ करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं लेकिन वहां जो आंकड़ा बना है, उत्तरांचल में जो आंकड़ा बना है कि 12 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब यह शासनतंत्र कैसा काम कर रहा है, यह आपको मानना चाहिये। पूरे देश में 40 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं वहां यह 12 प्रतिशत लोग बी0पी0एल0 के अन्तर्गत आने वाले हैं। इस कारण से उस क्षेत्र में बड़े अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने तो यह किया है, मायावती को लोग कोस रहे थे, उसने कहा कि 40 किलो अनाज कहीं से भी काट कर प्रति कार्ड हम देंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 21 मई के दिन पंतनगर गये थे। उन्होंने घोषणा की थी कि हम तीन-चार दिन में इस व्यवस्था को बदल देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप वही कर दीजिये जो नरसिंह राव जी के जमाने में था प्रति यूनिट 7 किलो चावल मिलता था और 10 किलो गेहूं मिलता था। इससे देश पर कोई बरबादी नहीं आ जाएगी। मैं अभी दक्षिणी राज्यों के दौरों पर गया था क्योंकि मैं खाद्य मंत्रालय की स्थाई समिति में हूँ। मैंने वहां देखा कि पूरे प्रदेशों में राशन कार्डों की संख्या उनकी जनसंख्या से ज्यादा है। लेकिन हमारे यहां स्थिति यह है कि हमारे लिए न्याय नहीं हो रहा है। यह कहा जा रहा है कि 12 प्रतिशत लोग बी0पी0एल हैं। यहां जो भी मंत्री बैठे हैं, मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएँ। उन्होंने वहां कहा था कि सात दिन के अन्दर कर देंगे, अब उनको गये हुए दो महीने बीत गए हैं। हमारे वहां के कमिश्नर का बयान “अमर उजाला” जो मेरठ से प्रकाशित हुआ है, उसमें निकाला है, 27 जुलाई को यह बयान प्रकाशित हुआ है —

“सुभाष कुमार, आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने बताया कि खाधान की समस्या अब पहले से काफी कम है। प्रदेश सरकार ने 18 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त खाधान का कोटा भेजा है। गढ़वाल में यह कोटा मैदानी जिलों के कोटे से काट कर भेजा गया है”।

मैं इसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि यह मैदानी जिलों से काटने की बात क्यों आई? इसलिए केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिये कि वह नीचे स्तर पर सुधार करें, व्यवस्था करे बी0पी0एल में लोगों को लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इससे उनका कल्याण होगा, उनके सामने तो संकट आने वाला है। अच्छा होता उनकी पहचान करके उनको सीधे नकद राशि दी जाती और एक ही दाम सब के खरीदने का होता तो ज्यादा सुविधाजनक होता। इसका

सारा राशन ब्लैक में जाएगा जैसे इस देश की नियति है, आम आदमी को मिलेगा नहीं जिसे सरकार देना चाहती है। इससे पीड़ा और पैदा होगी। इसलिए मैंने यह जो कोट किया है चावल के बारे में कमिश्नर ने कहा है, "गढ़वाल में इस समय चावल एवं सुपरफाइन चावल की काफी कमी है। विकासनगर डिपो एवं अन्य गोदामों में भी चावल नहीं है" अब यह कमिश्नर का कहना है। कमिश्नर की विज्ञापित है। इस पीड़ा को आप समझ सकते हैं। आजकल वहां बरसात हो रही है, रास्ते टूट गये हैं। अगर गोदामों में अन्न नहीं होगा तो वहां के समाज में क्या अवस्था आने वाली होगी? इसलिए मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ जो अपने रोजमर्रा के कामों में उलझी हुई है, सरकार थोड़ा उस क्षेत्र पर विचार करें क्योंकि खाद्य का विषय, पीओडीएस का विषय केन्द्र सरकार का विषय है। इसलिए केन्द्र उसका निदान करें। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : मैं भी संबद्ध करता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will take up rest of the Zero Hour mentions and Special Mentions after lunch. The House is adjourned for lunch for an hour.

The House, then, ad
journed for lunch at five
minutes past one of the
clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock.

**The Vice-chairman (Shri Sanatan Bisi):
in the Chair.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Hon. Members, before we take up the Zero Hour submissions and the Special Mentions, a Bill has to be introduced by the hon. Minister. I think I have the permission of the House. Mr. Minister, introduce your Bill.

THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL, 1997

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further

to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

The question was proposed.

SHRI TRILOKI NATH CHATUR-VEDI (Uttar Pradesh): Sir, this House has been worried' about the payment of wages. The Provident Fund itself has never been protected. There are so many complaints in this regard. If wages are not being paid, then what is the use of bringing this auxiliary Bill? Many public sector units are being closed. There are a lot of complaints with regard to PF in private sector. The Act which exists is not being enforced. What exactly is the purpose of this Bill, we cannot understand it.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: What is proposed is an increase of 2% on the rate of contribution.

SHRI TRILOKI NATH CHATUR-VEDI: More so, he was in the Ministry of Finance and now, he is in the Ministry of Labour ...*(interruptions)*... That is why, it is very relevant, we must know with what purpose this being brought when you are retrenching the workers, with regard to revival package, this morning there was so much *halla'gulla* in this House because the Government could not respond ...*(interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): The House is aware of it ...*(interruptions)*...

SHRI MP. VEERENDRA KUMAR: There may be arrears. That is a different questions. If the hon. Member so desires, I can compute the percentage of arrears and tell him. But this Bill will help lakhs of workers; lakhs of workers will get benefit out of it. All industries are not in a bad state ...*(interruptions)*...

SHRI TRILOKI NATH CHATUR VEDI: How?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): When we consider the Bill, we can discuss at length ...*(interruptions)*...